



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्रांधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1996/ज्येष्ठ 7, 1918

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1996/JYAISTHA 7, 1918

गृह मंत्रालय

श्रद्धिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1996

सा. का. नि. 228(श्र):— अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 को उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संघ राज्य धेन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य प्रावधान) नियमावली, 1995 के लिए वित्त आयोग को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को संघ राज्य धेन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) (दूसरा संघोधन) नियमावली, 1996 के लिए वित्त आयोग कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में लागू होंगे।

2. संघ राज्य धेन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995

के लिए वित्त आयोग में नियम 7 में उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

“(2) अध्यक्ष तथा सदस्य को कमशः 8000/-रु. तथा 7500/-रु. प्रतिमाह का निर्धारित वेतन दिया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है तो उसे उसके अन्तिम वेतन के बराबर एक निश्चित वेतन (मंहगाई भने समेत) अनुमत्य होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष अध्यक्ष आयोग का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन अध्यक्ष किसी राज्य सरकार के अधीन पड़ते किसी सेवा के लिए पेंशन (अयोग्यता अध्यक्ष घायल पेंशन के विवरित); प्राप्त कर रहा है तो आयोग में भेना के मंबंध में उसका निर्धारित वेतन उस पेंशन को राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई मरम्मत आयोग में अंशकालिक सेवा प्रवान करने के लिए नियुक्त फिशा जाता है तो उसे 4000/-रु. प्रतिमाह की निर्धारित फीम दी जाएगी”।

[फा. सं. यु.-11022/1/94-य.टी.एल.]
राजीव गांधी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:— प्रधान नियम सा. का. नि. 626 (ई) दिनांक 8-9-95 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और लद्दोपरान्त 12-1-96 के सा. का. नि. 28 (ई) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 1996

GSR 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules, further to amend the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous

Provisions) Rules, 1995, in rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Chairman and Member shall be paid a fixed salary of Rs. 8,000/- and Rs. 7,500/- respectively per month;

Provided that if a member happens to be a retired Government servant, he shall be allowed a fixed salary (inclusive of Dearness Allowance) equal to the last pay drawn:

Provided further that if the Chairman or any Member of the Commission, at the time of his appointment, is in receipt of pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his fixed salary in respect of service in the Commission shall be reduced by the amount of that pension:

Provided also that if a Member is appointed to render part-time service to the Commission, he shall be paid a fixed fee of Rs. 4,000 per month.

[F.No. U-11022/1/94-UTL]
RAJEEVA R. SHAH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96.